बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और मेहनतकश जनता की लूट के ख़िलाफ़!
रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जुझारू जनएकजुटता के लिए!

भगतसिंह जनअधिकार यात्रा

(12 मार्च, 2023 – 14 अप्रैल, 2023)

भाइयो, बहनो और साथियो!

हमारा देश इस वक़्त एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुज़र रहा है। बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। टैक्सों का पहाड़ लादकर महँगाई को चरम पर पहुँचा दिया गया है। श्रम की लूट को आसान बनाकर धन्नासेठों की तिजोरियाँ भरने का प्रबन्ध किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा शुरू की गयी उदारीकरण-निजीकरण की लुटेरी नीतियों की जानलेवा हवा मोदी राज में भयंकर ज़हरीले तूफ़ान में तब्दील हो चुकी है। **मोदी सरकार द्वारा जुमलों की तो ख़ूब बारिश हुई है लेकिन मेहनतकश जनता का जीवन नरक बन गया है। लोग बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती लूट से इस क़दर त्रस्त कभी नहीं हुए थे।** जनता को अपने अधिकारों को लेकर एकजुट होने से रोकने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाजपा द्वारा लोगों को साम्प्रदायिकता-जातिवाद-अन्धराष्ट्रवाद के फ़र्ज़ी मुद्दों में उलझाया जा रहा है। "राष्ट्रवाद" का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार सेना के जवानों के पेंशन, भत्ते और अब नौकरी तक निगल गयी। सच बोलने की बजाय आज मीडिया एक दंगाई की तरह साम्प्रदायिक उन्मादी ज़हर और झूठ उगल रहा है क्योंकि इसके बड़े हिस्से पर धन्नासेठों का क़ब्ज़ा है।

भाजपा व कांग्रेस के अलावा 'आप', सपा, बसपा, राजद, जद (यू), राकांपा, शिवसेना, अकाली दल, द्रमुक, अन्ना द्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आदि तमाम छोटे व क्षेत्रीय दल भी अलग-अलग ढंग से अपने-अपने राज्यों व क्षेत्रों में धन्नासेठों, धनी फ़ार्मरों, ठेकेदारों, दलालों, बिचौलियों, बिल्डरों आदि की ही सेवा करते हैं। ये भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर अपने-अपने तरीक़ों से हमें बाँटकर ही गोटियाँ लाल करते हैं। ख़ुद को मेहनतकश जनता का प्रतिनिधि बताने वाले सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल (लिबरेशन), एसयूसीआई जैसे दल बातें गर्मागर्म करते हैं पर सेवा शोषक वर्गों की ही करते हैं। ये बड़े धन्नासेठों के बजाय मुख्यत: छोटे और मँझोले मालिकों-व्यापारियों व धनी फ़ार्मरों की सेवा करते हैं। जहाँ इनकी या इनके गठबन्धनों की सरकारें हैं वहाँ भी उदारीकरण-निजीकरण की नीतियाँ धड़ल्ले से लागू हो रही हैं।

बेशक आज जनता को अपनी मुक्ति का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है लेकिन यह विकल्पहीनता ही हमारा भाग्य नहीं है। हमारा भरोसा है देश के बहादुर नौजवान, मेहनतकश मज़दूर-किसान आज के हालात को बदलने के लिए अवश्य आगे आयेंगे। इसीलिए अपने महान बलिदानी योद्धा पुरखों की क्रान्तिकारी विरासत से प्रेरित होकर हमने **'भगतसिंह जनअधिकार यात्रा'** की शुरुआत की है। **इस यात्रा का मक़सद समाज में नयी क्रान्तिकारी जागृति लाना और जनता को उसके असल मुद्दों के प्रति जागरूक और एकजुट करना है।**

रोज़गार पर मोदी सरकार का हमला जीने के हमारे अधिकार पर हमला है!

2014 में हर साल दो करोड़ रोज़गार देने का झाँसा देकर वोट माँगने वाले नरेन्द्र मोदी के राज में करोड़ों लोग अपने रोज़ी-रोज़गार से हाथ धो चुके हैं। नोटबन्दी, जीएसटी और कोरोना कालीन कुप्रबन्धन ने विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के कमेरों के पेट पर लात मारी है। जनता की कमाई पर खड़े सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर धन्नासेठों को सौंपा जा रहा है। इसका नतीजा भी सामने है, आज बेहतर शिक्षा और अच्छा इलाज पैसे वालों तक सीमित होकर रह गये हैं।

देश में इस समय तक़रीबन **32 करोड़ आबादी** बेरोज़गारी का दंश झेल रही है। **सरकारी महकमों में ख़ाली पड़े लाखों पदों को भरने के बजाय इन पदों को ही समाप्त किया जा रहा है। अग्निवीर स्कीम** का नाम देकर सेना तक में सरकार पक्के रोज़गार को हज़म कर गयी। **नयी शिक्षा नीति-2020** भी शिक्षा के साम्प्रदायीकरण, निजीकरण को बढ़ाने वाला व रोज़गार विरोधी दस्तावेज़ है। मोदी राज के पिछले आठ सालों के दौरान केन्द्र सरकार ने मात्र **7 लाख 22 हज़ार 311** लोगों को नौकरी दी है जबकि आवेदन करने वालों की संख्या **22 करोड़ 5 लाख 99 हज़ार 238** थी। भयंकर बेरोज़गारी की हताशा में लोग मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहे हैं। साल 2017-2021 तक चार सालों के दौरान **7,20,611** लोगों ने आत्महत्या की जिनमें ज़्यादातर दिहाड़ी व खेतिहर मज़दूर, ग़रीब किसान, छात्र-नौजवान और छोटा-मोटा "स्वरोज़गार" करने वाले लोग थे। **यही हैं "अच्छे दिन" जिनका गुणगान गला फाड़कर बिकाऊ गोदी मीडिया चौबीसों घण्टे करता रहता है? यदि सरकार जनता को रोज़गार जैसा अधिकार नहीं दे सकती है तो फिर वह है किसलिए?** बेरोज़गारी कोई क़ुदरती आपदा नहीं है न इसकी वजह आबादी है। अगर काम करने योग्य लोग हैं, विकास की ज़रूरत है और संसाधन हैं तो कोई कारण नहीं है कि लोग बेरोज़गार रहें। लेकिन एक मुनाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था में संसाधन भी बेकार पड़े रहते हैं, लोग भी बेकार घूमने को मजबूर होते हैं और विकास की मलाई केवल अमीरज़ादों को ही मिलती है, आम जनता को केवल जूठन हासिल होती है।

बढ़ती महँगाई की मार, ज़िम्मेदार मोदी सरकार!

सत्ता में आने से पहले नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने एक और जुमला जो उछाला था वह था "बहुत हुई महँगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार"! लेकिन अपने 8 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने महँगाई के मामले में जनता को दिन में तारे दिखा दिये हैं। खाद्य पदार्थों से लेकर रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी अपनी कमाई का **53 प्रतिशत** सिर्फ़ खाने पर ही ख़र्च कर देता है जबकि धनिकों की आय का सिर्फ़ **12 प्रतिशत** खाने पर ख़र्च होता है। व्यवस्थाजनित मन्दी का सारा बोझ आम जनता पर डाल दिया गया है। मोदी राज में 450 रुपये का गैस सिलेण्डर **1150**, 55 रुपये लीटर डीजल **95 रुपये** और 75 रुपये लीटर पेट्रोल **100 रुपये** पर पहुँच चुके हैं। **सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर सबसे ज़्यादा धन बटोरा है जिसका इस्तेमाल धन्नासेठों को टैक्स में छूट देने, नेताओं और बड़े अफ़सरों की मोटी तनख़्वाहों, पेंशनों और ऐय्याशी में होता है।** पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमत में होने वाली हर बढ़ोत्तरी से आम तौर पर महँगाई बढ़ती है। **सरकार जनता पर तो करों का बोझ लगातार बढ़ाती जा रही है वहीं दूसरी ओर पूँजीपतियों पर लगने वाले करों को घटाती जा रही है!** सरकारी व ग़ैर-सरकारी बैंकों ने जनता की गाढ़ी कमाई को अम्बानियों-अडानियों-टाटाओं-बिड़लाओं को ऋण के तौर पर दिया। **मोदी राज** में 2015 से 2021 तक **6 सालों** के बीच **11 लाख 19 हज़ार करोड़** के लोन बट्टे खाते में डाले गये जिसमें से मात्र एक लाख करोड़ की वसूली हुई है यानी **10 लाख 19 हज़ार करोड़ रुपये धन्नासेठों द्वारा सीधे हज़म कर लिए गये** जबकि 2004 से 2014 के 10 सालों में लोन माफ़ी की राशि 2 लाख 22 हज़ार करोड़ थी! **25 लाख से ज़्यादा का कर्ज़ लेकर न चुकाने वाले 'विलफुल डिफ़ॉल्टरों' की संख्या 15,000 तक पहुँच चुकी है, जनता का पैसा मारकर क़रीब 40 धनपशु तो देश छोड़कर ही भाग गये। क्या ऐसा सरकारी मिलीभगत के बिना सम्भव है? इस चोरी का ख़र्च भी महँगाई के तौर पर हम पर लाद दिया जाता है।** ज़ाहिर है बढ़ती महँगाई कुछ और नहीं बल्कि सरकार और लुटेरी जमात द्वारा जनता पर किया गया सीधा हमला है।

मुँह में राम बगल में छुरी : यही है "संस्कारी" भ्रष्टाचार का "चाल-चेहरा-चरित्र"!

भ्रष्टाचार पहले भी होता था पर सदाचार और संस्कार की मुरलिया बजाने वाली भाजपाई मण्डली ने खुले भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान स्थापित कर दिये हैं। 'न खाऊँगा न खाने दूँगा' के जुमले की पोल खुल चुकी है और खाना-खिलाना दोनों ज़ोरों पर है। **राफ़ेल सौदे, पीएम केयर, व्यापम घोटाले** से लेकर **अडानी के भयंकर भ्रष्टाचार** की पूरी परिघटना इसके जीते-जागते प्रमाण हैं। **हिण्डनबर्ग के ख़ुलासे ने साफ़ तौर पर अडानी के साथ मिलीभगत कर किये गये भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है।** मोदी राज में भाजपाइयों और इनके चहेते अमीरज़ादों-धन्नासेठों का विकास अवश्य हुआ है! इसीलिए तो धन्नासेठ भाजपा पर नोट बरसा रहे हैं! बदले में भाजपा साम्प्रदायिकता द्वारा जनता की एकता को तोड़ रही है और अमीरपरस्त नीतियों द्वारा धन्नोसेठों की पौ-बारह कर रही है। हमारे लिए सिर्फ़ यही है कि पहले हाड़तोड़ मेहनत कर सेठों की तिजोरियाँ भरें और फिर साम्प्रदायिक दंगों में एक-दूसरे का सिर फोड़ें! **ज़रा सोचिए कि साम्प्रदायिक दंगों और टकराहटों में कभी किसी धन्नासेठ-उन्मादी नेता-मन्त्री-नौकरशाह का घर क्यों नहीं जलता, वे तलवारें-त्रिशूल लेकर दौड़ते और आगज़नी करते क्यों नहीं दिखते? उनके बेटों को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर नोट छापने का अवसर दिया जाता है और आपके बेटे-बेटियों के हाथ में धार्मिक भावनाएँ भड़काकर दंगे-फ़साद का सामान पकड़ा दिया जाता है। ज़रा सोचिए कि आख़िर कब तक हम मूर्ख बनकर इस साज़िश का शिकार होते रहेंगे?**

ग़रीबी और आर्थिक असमानता रिकॉर्डतोड़ स्तर पर

हमारे देश में ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या **23 करोड़** तक पहुँच चुकी है जो दुनिया में सबसे अधिक है। वैसे ये ग़रीबी रेखा ख़ुद एक मज़ाक है। यह भुखमरी रेखा है। अक्टूबर 2022 के वैश्विक भूख सूचकांक में 121 देशों की सूची में हमारा देश **107वें स्थान** पर है! साल 2019 के अन्तिम आँकड़ों के अनुसार यहाँ एक साल में **8,24,000 शिशु मौत का शिकार** हुए। **यानी हर दो मिनट में तीन बच्चों की मौत!** भुखमरी और बालमृत्युदर में हम अफ़्रीका के ग़रीब देशों से भी पीछे हैं। 1981 में भारत के सबसे ऊपर के **10 प्रतिशत** अमीरों की सम्पत्ति देश की कुल सम्पत्ति की **45 फ़ीसदी** थी जो 2012 में बढ़कर **63 फ़ीसदी** और 2022 में बढ़कर **80 फ़ीसदी** से भी अधिक हो गयी। इस समय देश की कुल सम्पत्ति के **90 प्रतिशत** पर ऊपर के सिर्फ़ **30 फ़ीसदी** लोग कुण्डली मारे बैठे हैं। सबसे ऊपर के **1 प्रतिशत** धन्नासेठों के पास देश की **40 फ़ीसदी** से भी अधिक सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है जबकि नीचे से **50 प्रतिशत** लोगों के पास कुल सम्पत्ति का मात्र **3 फ़ीसदी** है। **एक तरफ़ धन-दौलत का बढ़ता ढेर और दूसरी तरफ़ भूख से दम तोड़ते बच्चे!** यही है मौजूदा मुनाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था का सच जिसके बारे में भगतसिंह आगाह किया करते थे।

साम्प्रदायिक कट्टरता पर हल्ला बोल!

जनता अपने उपरोक्त असली मुद्दों के बारे में न सोच सके इसके लिए ही **साम्प्रदायिक कट्टरता के भस्मासुर** को खाद-पानी देकर खड़ा किया गया है। अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो-राज करो' की साम्प्रदायिक नीति के तहत जनता को बाँटा और राज किया व अन्त में देश का विभाजन कर डाला। केवल मुस्लिम लीग ने ही नहीं बल्कि आरएसएस के आदर्श सावरकर और हिन्दू महासभा ने भी 'दो राष्ट्र सिद्धान्त' की हिमायत की थी जोकि देश को बँटवारे की ओर ले गया। आज़ादी के बाद सत्तासीन हुए अमीरज़ादों के नुमाइन्दों ने भी जनता को आपस में लड़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस और विभिन्न क्षेत्रीय दल भी नरम साम्प्रदायिक कार्ड खेलते रहे या फिर नकली धर्मनिरपेक्षता की माला फेरते रहे हैं। संघ परिवार और भाजपा का तो एजेण्डा ही साम्प्रदायिक नफ़रत फैलाकर जनान्दोलनों को कमज़ोर करना रहा है। बदले में इसे धन्नासेठों द्वारा बोरियाँ भर-भरकर रुपये मिलते हैं। 2014 में सत्ता में आने से पहले ही सेठों के नोट भाजपा पर बरसने शुरू हो गये थे। **2012-13 से 2015-16 तक पाँच राष्ट्रीय पार्टियों को 956 करोड़ 57 लाख रुपये चन्दा कॉर्पोरेट घरानों से प्राप्त हुआ जिसका 74 प्रतिशत हिस्सा यानी 705 करोड़ 81 लाख रुपये अकेले भाजपा को मिला!** भाजपा को वर्ष 2021-22 के दौरान ही **615 करोड़ रुपये** कॉर्पोरेट चन्दा मिला है जोकि बाकी तमाम चुनावी पार्टियों को मिले कुल चन्दे से भी कई गुना ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2020 में भाजपा की कुल घोषित सम्पत्ति **4847 करोड़ 78 लाख रुपये** थी, जबकि 2017 में यह 1213 करोड़ थी। इसीलिए कहा गया है **जो जिसका खायेगा उसी का हुक्म बजायेगा!** पिछली सरकारों ने भी पूँजीपति वर्ग के ही किसी न किसी हिस्से की ही सेवा की है लेकिन संकट के दौर में धन्नासेठों को भाजपा की ज़रूरत है जो जनता को असल मुद्दों से भटका सके, धर्म के नाम पर लड़ा सके और उसका दमन कर सके। **भाजपा और संघ परिवार द्वारा परोसी गयी फ़ासीवादी साम्प्रदायिक कट्टरता ही ओवैसी, पी.एफ़.आई., अमृतपाल जैसी साम्प्रदायिक कट्टरपन्थी ताक़तों को भी फलने-फूलने का मौका देती है। साम्प्रदायिक व धार्मिक कट्टरपन्थी राजनीति हमेशा ही आम लोगों के जान-माल पर आफ़त बनकर टूटती है। इससे कभी किसी योगी, किसी ओवैसी का घर नहीं जलता।**

भगतसिंह ने कितना सटीक कहा था कि लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की ज़रूरत होती है। यह बात आज भी उतनी ही सच है। मेहनतकश जनता चाहे किसी भी जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र की हो उसकी समस्याएँ एक हैं, उसे लूटने वाली ताक़तें भी एक हैं। हम अपनी एकजुटता बनाकर संघर्ष करेंगे तो अपने हक़ हासिल कर सकते हैं। **हमें सच्ची धर्मनिरपेक्षता के लिए धर्म के राजनीति व सामाजिक जीवन से पूर्ण विलगाव की माँग उठानी चाहिए। इसके बिना धार्मिक कट्टरता और फ़िरकापरस्ती का दानव हमें निगल जायेगा जैसा कि कई देशों में हुआ भी है। हमें हर प्रकार की साम्प्रदायिकता को नकार देना चाहिए।**

• **साथियो! हमें जीवन से जुड़े असल मुद्दों पर आपसी एकजुटता बनाते हुए एक नयी शुरुआत करनी होगी।** यदि हमें शिक्षा, रोज़गार, चिकित्सा, आवास, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा, जनवादी अधिकार, सच्चे सेक्युलरिज़्म और जनपक्षधर संस्कृति व मूल्य देने में मौजूदा व्यवस्था नाकाम है तो हमें इसे हटाकर एक नयी जनपक्षधर व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें उत्पादन, राजकाज और समाज के पूरे ढाँचे पर उत्पादक मेहनतकश जनता के समूहों का नियन्त्रण हो। **लेकिन इस दूरगामी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत अपने बुनियादी अधिकारों यानी शिक्षा, रोज़गार, चिकित्सा, आवास पर सरकार को घेरने और उन्हें हासिल करने के संघर्ष से करनी होगी।** इसी संघर्ष के लिए जनता को जगाने हेतु **भगतसिंह जनअधिकार यात्रा** की शुरुआत की गयी है। यह मुहिम आपके लिए है और आपकी अपनी है। **आप भी भगतसिंह जनअधिकार यात्रा का हिस्सा ज़रूर बनें।**

हमारी प्रमुख माँगें :

⇨शिक्षा-रोज़गार-स्वास्थ्य-आवास मौलिक अधिकार घोषित हों। निजीकरण पर रोक लगे। **भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून** पारित करो, रोज़गार न दे पाने की सूरत में 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता दिया जाये। केन्द्र व राज्य सरकारों के सभी ख़ाली पद शीघ्र भरो। 'अग्निवीर' योजना को तत्काल रद्द कर सेना में पक्की भरती की व्यवस्था बहाल की जाये।

⇨सभी श्रम क़ानूनों को सख़्ती से लागू करो, प्रस्तावित चार 'लेबर कोड्स' रद्द करो। ग्रामीण मज़दूरों को भी श्रम क़ानूनों के अन्तर्गत लाया जाये। 'पुरानी पेंशन स्कीम' बहाल करो। **ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर नियमित प्रकृति के कामों पर पक्के रोज़गार का प्रबन्ध करो।**

⇨महँगाई पर रोक लगाने के लिए **सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया जाये** और बढ़ती सम्पत्ति के आधार पर **प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों** की व्यवस्था को मज़बूती के साथ लागू किया जाये।

⇨**मनरेगा योजना** को सख़्ती से लागू किया जाये, इसके तहत पूरे साल का काम देने का प्रावधान किया जाये और इसके काम पर कम-से-कम न्यूनतम वेतन जितनी राशि प्रदान की जाये।

⇨**ग़रीब और मँझोले किसानों के लिए** बीज, खाद, बिजली, आदि पर सब्सिडी की समुचित व्यवस्था हेतु अमीर वर्गों पर **विशेष कर** लगाये जायें, सिंचाई की सरकारी व्यवस्था और **संस्थागत ऋण** का भी समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

⇨"सर्वधर्म समभाव" की नकली धर्मनिरपेक्षता की जगह **सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य** को सुनिश्चित करने के लिए क़ानून लाया जाये। किसी भी नेता या पार्टी द्वारा धर्म, समुदाय या आस्था का सार्वजनिक जीवन में किसी भी रूप में उल्लेख व इस्तेमाल करना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये।

⇨**छुआछूत** ही नहीं बल्कि **हर प्रकार से जातिगत भेदभाव को संवैधानिक संशोधन करके दण्डनीय अपराध** घोषित किया जाये।

⇨चुनावी दलों व सरकार द्वारा किये जाने वाले **भ्रष्टाचार पर रोक लगे और इनके पब्लिक ऑडिट व जाँच की व्यवस्था** की जाये।

⇨**स्त्रियों के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के हर रूप को समाप्त करो, इसके लिए सख़्त क़ानून लाये जायें।**

⇨**धार्मिक व जातिगत वैमनस्य भड़काने वाले तथा साम्प्रदायिक हिंसा व मॉब लिंचिंग में सक्रिय हर प्रकार के संगठनों और दलों पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाकर इन्हें आतंकवादी घोषित किया जाये** और इनके नेताओं व गुर्गों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाये।

साथियो, ये कुछ बेहद बुनियादी माँगें हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन से जुड़ी हैं। **इनमें से कोई भी माँग ऐसी नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता हो। वास्तव में इनमें से कई अधिकार दुनिया के बहुत से देशों में जनता को हासिल हैं जो उसने लड़कर हासिल किये हैं। तो फिर हमारे यहाँ ये सम्भव क्यों नहीं हो सकता है?** यदि कोई सरकार जनता की बुनियादी ज़रूरतों से ही मुँह मोड़ती है तो उसे सरकार में बने रहने का कोई हक़ नहीं है। यदि आप हमसे सहमत हैं तो उपरोक्त माँगों पर ग़ौर करें, इनपर एकजुट-संगठित हों और इन्हें हासिल करने के संघर्ष में हमारा साथ दें। यह वक़्त की ज़रूरत है कि धर्म-जाति-क्षेत्र-भाषा आदि के बँटवारों को भूलकर हम एक साथ आयें। यदि आज भी हम नहीं उठ खड़े होते तो भविष्य हमें कभी माफ़ नहीं करेगा।

अन्धकार का युग बीतेगा! जो लड़ेगा वो जीतेगा!!

BHAGAT SINGH JAN ADHIKAR YATRA
BSJAY

●भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI)

●नौजवान भारत सभा ●दिशा छात्र संगठन ●बिगुल मज़दूर दस्ता

सम्पर्क:- दिल्ली: 9289498250, 9693469694; उत्तर प्रदेश: 8858288593, 9891951393; हरियाणा: 8010156365, 8685030984; महाराष्ट्र: 7798364729, 9619039793; बिहार: 6297974751, 7070571498; उत्तराखण्ड: 9971158783, 7042740669; पंजाब: 9888080820; आन्ध्र प्रदेश: 7995828171, 8500208259; तेलंगाना: 9971196111; चण्डीगढ़: 8196803093

@bsjayatra 9582712837

भगतसिंह जनअधिकार यात्रा के लिए नौभास के योगेश द्वारा जारी, तिथि 7 मार्च, 2023